आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 09.07.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- देहरादून में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में साइबर और आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए अहम फैसले लिए गए।
- निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखवीर सिंह सन्धु ने प्रदेश में युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए।
- उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विशेषज्ञ दल हिमाचल प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न आपदा स्थितियों और आपदा प्रबंधन उपायों का अध्ययन करेगा।
- चम्पावत के माँ बाराही धाम देवीधुरा में विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेला 5 अगस्त से शुरू होगा।

साइबर अपराध रोकथाम / सुरक्षा

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में कल सचिवालय में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 25वीं बैठक हुई, जिसमें साइबर और आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए अहम फैसले लिए गए। बैठक में श्री बर्धन ने आर्थिक अपराध इकाई को एक सशक्त और स्वतंत्र एजेंसी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि वित्तीय और साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों, बैंकों और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। इस दौरान प्राथमिकी दर्ज करने, जांच, चार्जशीट और अनुपालन की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया गया।
मुख्य सचित ने यह भी निर्देश दिया कि साइबर अपराध समन्वय केंद्र में बैंक प्रतिनिधियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी वेबसाइट को तुरंत ब्लॉक किया जा सके और लोगों की पूंजी सुरक्षित रहे।
इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि जो संस्थाएं या फर्में जनता से निवेश के रूप में पूंजी जुटा रही हैं, उनका 'नियमत निवेश' पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। इसके लिए सभी बैंकों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए।

निर्वाचन

निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखवीर सिंह सन्धु ने उत्तराखंड में युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों के लिए राज्य और जिला स्तर पर प्रभावी प्रशिक्षण व्यवस्था की जाए और इसके लिए मास्टर प्रशिक्षकों को विशेष रूप से तैयार किया जाए।
देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक में डॉ. सन्धु ने निर्वाचन गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने विस्तृत प्रस्तुति दी और सुझाव दिया कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक–एक प्रशिक्षण केंद्र चिन्हित किए जाएं, जहां समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें।
चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों से समन्वय बनाकर बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम का खाका तैयार कर लिया गया है। आयोग के नए निर्देशों के अनुसार, दो किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी वाले मतदान केंद्रों या बारह सौ से अधिक मतदाताओं वाले बूथों को ध्यान में रखते हुए राज्य में लगभग एक हजार नए मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

नंदा देवी राजजात– तैयारियां

वर्ष 2026 में प्रस्तावित नंदा देवी राजजात यात्रा को पारंपरिक स्वरूप में सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में यात्रा संचालन के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने, सफाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस योजना बनाने तथा पर्यटन विभाग को यात्रा का डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंट्री तैयार करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने चमोली के जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि सभी संबंधित विभागों और हितधारकों के साथ समन्वय कर एस०ओ०पी में व्यवस्था, सुरक्षा, संचालन और नियंत्रण से जुड़ी सभी बातों को शामिल किया जाए। उन्होंने अपशिष्ट, सेप्टिक और स्वच्छता प्रबंधन की समुचित योजना तैयार करने पर भी जोर दिया।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यात्रा की पारंपरिक मौलिकता हर हाल में बनाए रखी जाए। यात्रा से जुड़े स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों को अलग–अलग श्रेणियों में प्रस्तावित किया जाए और जरूरत के अनुसार सप्लीमेंट्री बजट की मांग की जाए, जबकि नियमित कार्य विभागीय बजट से ही पूरे हों।

मुख्य सचिव ने चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियोंसे भी फीडबैक लेते हुए यात्रा तैयारियों से जुड़ी आवश्यकताओं की जानकारी ली।

कार्रवाई

प्रदेश में भू अधिनियम के तहत भूमि क्रय की अनुमति के बावजूद भू उपयोग उल्लंघन के मामलों में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। अब तक भू उपयोग के उल्लंघन के चलते कुल तीन दशमलव शून्य–शून्य छह हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार में निहित की जा चुकी है।

उत्तराखंड भूमि अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दी गई 532 भूमि क्रय अनुमतियों के सापेक्ष 88 मामलों में उल्लंघन सामने आए हैं, जिनमें से 42 मामलों में वाद दायर किए गए हैं। वहीं, अन्य प्रावधानों के तहत दी गई 963 अनुमतियों में 172 मामलों में उल्लंघन पाया गया और इनमें से 112 मामलों में कानूनी कार्रवाई की गई है।

राज्य में जिन जमीनों को सरकार में निहित किया गया है, उनमें बागेश्वर के कपकोट, उधमसिंहनगर के रुद्रपुर, नैनीताल के कैंची धाम, अल्मोड़ा के दिगोटी द्वाराहाट, कटारमल चौखुटिया और कोट्यूड़ा क्षेत्र की भूमि शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में सशक्त भू कानून लागू हो चुका है और कृषि व उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगा दी गई है। भू अधिनियम के उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर ऐसी जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जा रहा है।

वि□ोशज्ञ दल

उत्तराखंड सरकार ने हिमाचल प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न आपदा स्थितियों और वहां के आपदा प्रबंधन उपायों का अध्ययन करने के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विशेषज्ञ दल भेजने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन को यह निर्देश दिए ताकि हिमाचल के अनुभवों के आधार पर उत्तराखंड में प्रभावी रणनीति बनाई जा सके।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर मुख्य सचिव ने मानसून की स्थिति, बारिश के आंकड़े और भूस्खलन से बंद सड़कों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोला जाए और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में आवश्यक उपकरण पहले से तैनात रहें। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि आपदा स्थल पर 15 मिनट के भीतर जेसीबी और अन्य संसाधन पहुंच जाएं।

बग्वाल मेला

चम्पावत के माँ बाराही धाम देवीधुरा में विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेला 5 अगस्त से 16 अगस्त तक आयोजित होगा। मुख्य पर्व ''बग्वाल'' 9 अगस्त को पारंपरिक ढंग से मनाया जाएगा। मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली और स्वच्छता व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने बताया कि यह मेला देश–विदेश से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए मंदिर समिति और अधिकारियों की बैठक में आवश्यक चर्चा की गई।

पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि मेले में एक से डेढ़ लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सुरक्षा के लिए सीओ चम्पावत को नोडल अधिकारी बनाया गया है। यातायात व्यवस्था और व्यापारियों का सत्यापन भी किया जाएगा।

समझौता ज्ञापन

चमोली जिले के भराड़ीसैंण स्थित अंतरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, जौलीग्रांट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य राज्य में नीति निर्माण, अनुसंधान और प्रशिक्षण को मजबूती देना है।

समझौते के तहत पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक शासन जैसे विषयों पर संयुक्त परियोजनाएं चलाई जाएंगी। साथ ही विधायकों, पंचायत प्रतिनिधियों और युवाओं के लिए प्रशिक्षण व नीति संवाद भी होंगे।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूड़ी भूषण ने कहा कि यह समझौता उत्तराखंड को एक जन–केंद्रित नीति राजधानी बनाने की दिशा में मील का पत्थर है। भराड़ीसैंण को एक पॉलिसी इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां शोध और परंपरा के साथ व्यवहारिक नीतियां गढ़ी जाएंगी।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव

त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्नता को लेकर देहरादून के जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने कल विभिन्न प्रकोष्ठों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्वाचन संबंधी सभी कार्य तय समय पर और बिना किसी त्रुटि के पूरे किए जाएं।

जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालन हो और आदर्श आचार संहिता का पूरी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बारिश को देखते हुए सड़कों पर मैनपावर और मशीनरी की पर्याप्त तैनाती, वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं।

उन्होंने सभी पोलिंग बूथों पर बिजली, पानी, शौचालय और फर्नीचर जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा और एसडीएम से एक बार फिर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही मतदान पार्टियों की रवानगी, स्ट्रांग रूम, मतगणना और हेल्थ किट संबंधी योजनाओं को भी समय पर पूरा करने को कहा।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर...

उत्तराखंड में कल गुरुवार से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस समाचार को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता है– आंतकवादी खतरे को मद्देनजर यात्रा के लिए कड़ी व्यवस्था की जाएगी। अमर उजाला लिखता है – सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एटीएस और विशेष सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश।

एक अन्य खबर पर अमर उजाला लिखता है– अतिवृष्टि से निपटने के तरीके सीखने हिमाचल जाएगा दल। मुख्य सचिव ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ बैठक में दिए निर्देश।

चमोली जिले के धुर्सा गांव में अतिवृष्टि से कई मकान ध्वस्त हुए। इस खबर पर दैनिक जागरण लिखता है – चमोली में बादल फटा, 18 भवन क्षतिग्रस्त, खेत बहे।

राज्य में भू–कानून से संबंधित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान को हिन्दुस्तान, नवोदय टाइम्स समेत अन्य समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है।